PRABHAT KHABAR, Ranchi, 8.9.2017
Page No. 8, Size:(31.59)cms X (14.88)cms.

आधार कार्ड की सीडिंग शत प्रतिशत हुई : चौबे

प्रमुख संवाददाता ▸ रांची

राज्य में शत प्रतिशत उपभोक्ताओं की आधार सीडिंग कर ली गयी है. केवल 19 हजार आदिम जनजातियों की आधार सीडिंग नहीं हुई है, लेकिन इसका भी इनरॉलमेंट कर दिया गया है. जल्द ही इसकी भी आधार सीडिंग हो जायेगी. यह जानकारी खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने दी. श्री चौबे ने सरकार के 1000 दिनों में हुए विभाग की उपलब्धियों से पत्रकारों को अवगत कराया.

श्री चौबे ने कहा कि राज्य में खाद्यान्न का वितरण 97 हजार एमटी से बढ़ कर 1.45 लाख एमटी हो गया है. उन्होंने बताया कि राशन डीलरों का कमीशन 26 पैसे से बढ़ा कर एक रुपये प्रति किलो कर दिया गया है. पहले 35 लाख बीपीएल परिवार को मुफ्त नमक दे रहे थे. अब 56 लाख परिवार को डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण किया जा रहा है.

हटाये गये 11.64 लाख फरजी कार्ड

सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि 1000 दिनों में 11.64 लाख डुप्लीकेट, अयोग्य व फरजी कार्ड पाये गये और उसे रद्द किया गया. वहीं, 9.31 नये परिवारों को इस योजना से जोड़ दिया गया है. यह विभाग की बड़ी उपलब्धि है.

अनियमितताओं को देखते हुए सारा काम कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है. जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से खाद्यान्नों की ट्रांसपोर्टिंग हो रही है. इ-पॉश के माध्यम से बायोमिट्रिक्स का इस्तेमाल कर लाभुकों को खाद्यान्न दिया जा रहा है. 25500 दुकानों में इ-पॉश के माध्यम से 56 लाख लाभुकों को राशन दिया जा रहा है. इससे चोरी समाप्त हुई है.

सचिव विनय कुमार चौबे.

225 करोड़ की बचत हुई

उन्होंने बताया कि कार्ड शुद्धिकरण व इ पॉस के वितरण से 72 हजार एमटी खाद्यान्न की बचत हुई है. इससे केंद्र व राज्य सरकार को करीब 225 करोड़ रुपये की बचत हुई है. यह आंकड़ा अगस्त मह की है.

उज्ज्वला में आठ लाख परिवारों को लाभ दिया

उज्ज्वला योजना के तहत कुल आठ लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है. कुल 26 लाख लोगों को इससे लाभान्वित करना है. यह काम मार्च 2018 तक कर लिया जायेगा.

योजनाएं केवल झारखंड में ही चालू की गयी : सचिव ने बताया कि जुलाई माह से झारखंड में केरोसिन वितरण की प्रक्रिया में डीबीटी शुरू की गयी है. यानी सब्सीडी की राशि उपभोक्ता के खाता में सीधे जायेगा. इसके साथ ही पीटीजी डाकिया योजना शुरू की गयी. इस के तहत 80 हजार आदिम जनजातिय परिवारों को घर में पहुंचा कर 35 किलो अनाज दिया जा रहा है.

नगड़ी से शुरू होगा खाद्यान्न का डीबीटी : नगड़ी प्रखंड देश का पहला प्रखंड होगा, जहां एक अक्तूबर से खाद्यान्न में डीबीटी चालू किया जायेगा. बाजार दर से उपभोक्ता राशन डीलर से चावल खरीदेंगे और उन्हें सब्सीडी का पैसा खाता में मिल जायेगा. उपभोक्ताओं के लिए खाता में सब्सीडी की राशि एडवांस में रख दी जायेगी.

धान अधिप्राप्ति में 50 फीसदी सफल रहे

धान अधिप्राप्ति मामले में विभाग ने मात्र 50 फीसदी ही उपलब्धि हासिल की है. सचिव ने बताया कि कमियों को चिह्नित कर लिया गया है. अब उसे दूर किया जा रहा है. चार लाख के लक्ष्य की तुलना में कुल दो लाख ही धान की अधिप्राप्ति की जा सकी. सचिव ने कहा कि चावल मिल, ट्रांसपोर्टेशन व गोदामों की क्षमता सहित कई कारण फेल होने के रहे हैं.

जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर

सचिव ने कहा कि विभाग द्वारा उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 0651-7122723, +918969583111 जारी किया गया है, जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देती है. वहीं, धान अधिप्राप्ति के लिए बोनस भुगतान योजना के तहत किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1470 रुपये के अतिरिक्त 130 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है.